



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय), अपीलस(

Office of the Commissioner,

केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद आयुक्तालय

Central GST, Appeal Commissionerate- Ahmedabad

जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.

CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015

☎ 26305065-079 : टैलेफैक्स 26305136 - 079 :



रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(GST)82/Ahd-South/2019-20 / 13121 70 / 3125

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-JC-010-2019-20
दिनांक Date : 20-11-2019 जारी करने की तारीख Date of Issue 28/11/2019

श्री मुकेश राठोर संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri. Mukesh Rathor, Joint. Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No 127/Div-III/A'bad-S/2019-20 दिनांक: 21.05.2019 issued by
Assistant Commissioner, Div-III, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
Anar MCAT Advanced Electronic Chemicals Pvt Ltd
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal issued under the Central Excise Act 1944, may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

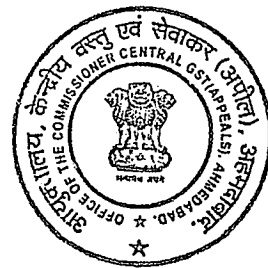
(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 1 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित हैं।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

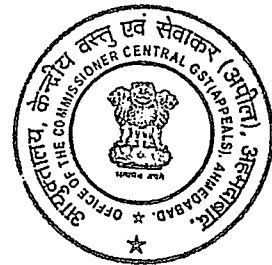
सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 112 के अंतर्गत:-

Under Section 112 of CGST act 2017 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद -380004

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

6(I) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

II. Any person aggrieved by an Order-In-Appeal issued under the Central Goods and Services Tax Act,2017/Integrated Goods and Services Tax Act,2017/ Goods and Services Tax(Compensation to states) Act,2017, may file an appeal before the appropriate authority



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Anar MCAT Advanced Electronic Chemicals Pvt. Ltd., Plot no 12,14 GIDC Industrial Estate Phase-1, Vatva, Ahmedabad-382445 (in short 'appellant') against Order-in-Original No.127/2019-20 dated 21.05.2019 (in short 'impugned letter') passed by the Assistant Commissioner, CGST Division-III, Ahmedabad South (in short 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that the appellants were holding erstwhile GSTIN registration number 24AAACCE9835A1ZZ. The appellants had filed a refund claim of Rs.11,33,280/- (IGST) on 23.07.2018 before the Assistant Commissioner, CGST Division-III, Ahmedabad South that they have made export with payment of IGST in the month of July-2018 and at the time of filling GSTR-3B, the same is erroneously paid tax in Table 3.1 (a) i.e. Tax on local outward supplies, instead of 3.1 (b) i.e. Zero Rated Supply. However the same is correctly shown in GSTR-1. After the knowing of the same they have paid the IGST again in correct table i.e. 3.1(b) of GSTR-3B and file the refund application for the amount erroneously paid in July-2018, before the adjudicating authority on the ground that they had wrongly paid IGST under section 54 of IGST Act-2017, the original adjudicating authority rejected the entire claim of refund vide impugned order.

3. Being aggrieved with the impugned order the appellants have preferred the present appeal. And contended that they stated that they have made export with payment of IGST in the month of July-2018 and at the time of filling GSTR-3B, the same is erroneously paid tax in Table 3.1 (a) i.e. Tax on local outward supplies, instead of 3.1 (b) i.e. Zero Rated Supply. However the same is correctly shown in GSTR-1. After knowing that they have paid in the wrongly in the table 3.1(a), they paid IGST again in correct table i.e. 3.1(b) of GSTR-3B and filed the refund application for the amount erroneously paid in July-2018, they have no local sales and hence there is no liability of IGST, the IGST paid wrongly cannot be adjusted (Set Off) against any liability.

4. Personal hearing in the matter was granted and held on 04.11.2019. Shri Dhaval Joshipura, Administrative Officer, appeared before me on behalf of the appellants and reiterated the contents of Appeal Memorandum.

5. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of appeal in the Appeal Memorandum and oral submissions made by the appellants at the time of personal hearing. I find that the adjudicating authority has verified the same and confirmed the fact in respect to Rule



89(2) of the Central/Gujarat State Goods and Services Tax Rule, 2017, documentary evidence in Annexure 1 in Form GSTRFD-01 are required to be submitted along with the refund in order to establish the refund have been detailed and this rule does not say about the admissibility/inadmissibility of the refund. I find the relevant paragraph of my O-I-A for more clarification of Circular No. 26/26/2017-GST dated 29.12.2017 at Para 4 clearly states;

" It is clarified that as return in **FORM GSTR-3B** do not contain provisions for reporting of differential figures for past month(s), the said figures may be reported on net basis alongwith the values for current month itself in appropriate tables i.e. Table No. 3.1, 3.2, 4 and 5, as the case may be. It may be noted that while making adjustment in the output tax liability or input tax credit, there can be no negative entries in the **FORM GSTR-3B**. The amount remaining for adjustment, if any, may be adjusted in the return(s) in FORM GSTR-3B of subsequent month(s) and, in cases where such adjustment is not feasible, refund may be claimed. Where adjustments have been made in **FORM GSTR-3B** of multiple months, corresponding adjustments in **FORM GSTR-1** should also preferably be made in the corresponding months."

6. I also find Page 6 of Circular No. 26/26/2017-GST dated 29.12.2017, the issue involve in the instant case has been clarified with proper illustration. Important gist, relevant to the instant case, is as under:

Issue	Solution provided in the said circular
All liabilities were offset by debiting the cash and credit ledger. No action was taken after this step	Liability may be adjusted in return of subsequent month(s) or refund may be claimed where adjustment is not feasible.
Company B had reported an inter-State sale but realized that the same sale was counted twice and hence was not to be reported or taxed. But the return form was already filed and no change could be done to reduce the liabilities. What can company B do?	In this case, they may reduce this liability in the return of subsequent months or claim refund of the same.

Hence, it is clear that this Circular gives the Provision to adjust in return of subsequent month(s).



The appellant has not produced any evidence to show that the liability has been or not adjusted in the subsequent months in their returns as per provisions of para 4 of the said circular above

7. Therefore, in view of the discussion held above, I held the impugned order and reject the appeals filed by the appellants.
8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
8. The appeal filed by the appellants stands disposed off in above terms.

(Mukesh Rathore)
Jt. Commissioner (Appeals),
AHMEDABAD.

Dated: 20/11/2019

ATTESTED

(Birjesh Sharma)
Superintendent,
CGST (APPEALS), AHMEDABAD.



To,

M/s. Anar MCAT Advanced Electronic Chemicals Pvt. Ltd.,
Plot no 12, 14 GIDC Industrial Estate Phase-1,
Vatva, Ahmedabad-382445.

Copy to:-

- (1) The Pr. Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone.
- (2) The Pr. Commissioner, CGST, Ahmedabad South (RRA Section).
- (3) The Asstt. Commissioner, CGST, Division- III, Ahmedabad South.
- (4) The Asstt. Commissioner(System), CGST, Ahmedabad South.
(for uploading OIA on website)
- (5) Guard file
- (6) P.A. file.